This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 / 05 भाद्रपद, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 अगस्त , 2021

संख्या एफ.डी.एस.–(ए)3–2 / 2019.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 2(19), 28(2)(ख), 33(3), 38(2), 41, 42(3), 46(3), 70(5) और धारा 102 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (छ), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ढ), (ण) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (साधारण) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है ;

(ख) ''आयोग'' से, यथास्थिति, जिला आयोग और राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्यक्ष'' से, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) ''धारा'' से, अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ङ) ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. **जिला आयोग की बैठक का स्थान.**––जिला आयोग का कार्यालय जिला के मुख्यालय में अवस्थित होगा और जहां राज्य सरकार एकल जिला आयोग, जो एक से अधिक जिलों में अधिकारिता रखता हो, की स्थापना करने का विनिश्चय करती है तो यह इस प्रकार स्थापित जिला आयोग का स्थान और अधिकारिता अधिसूचित करेगी।

4. **जिला आयोग और राज्य आयोग के कार्य दिवस और काम के घण्टे.**––जिला आयोग और राज्य आयोग के कार्य दिवस और काम के घण्टे वही होंगे जैसे कि राज्य के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय के हैं।

5. **मुहर और प्रतीक.**––जिला आयोग और राज्य आयोग की आधिकारिक मुहर और प्रतीक ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

6. **जिला आयोग और राज्य आयोग की बैठकें.**––जिला आयोग और राज्य आयोग का अध्यक्ष उपभोक्ता–मामलों के त्वरित निपटान के लिए उस आयोग की बैठकें, जब कभी आवश्यक हों आयोजित करेगा।

7. **स्थापित की जाने वाली लोक उपयोगी सेवाएं.**––लोक उपयोगी सेवाएं, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (19) के प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाएंगी।

8. **जिला आयोग में सदस्यों की संख्या.**––जिला आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष महिला होगी।

9. **जिला आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारिवृंद.**––जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों, जो उस स्थान पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को लागू हों, द्वारा विनियमित की जाएंगी। ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों को संदेय वेतन राज्य सरकार की समेकित निधि से चुकता किया जाएगा।

10. **विश्लेषण और परीक्षण के लिए जिला आयोग और राज्य आयोग द्वारा माल के अधिप्रमाणन की रीति.**––(1) जिला आयोग और राज्य आयोग परिवादी को परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए स्वच्छ

पात्रों (कंटेनरज़) में समुचित रूप से लगाए गए काम / डाट सहित माल के एक या एक से अधिक नमूने उपलब्ध करवाने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) ऐसे माल के नमूने प्राप्त करने पर, जिला आयोग और राज्य आयोग उनको सीलबन्द करेगा और निम्नलिखित सूचनाओं वाले पात्रों (कंटेनरों) पर नामपत्र (लेबिल) लगाएगा, अर्थात्:–

(क) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम और पता, जिसको विश्लेषण और परीक्षण के लिए नमूना भेजा जाना है;

(ख) यथास्थिति, जिला आयोग और राज्य आयोग का नाम और पता;

(ग) केस संख्याय; और

(घ) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग की आधिकारिक मुहर।

(3) सीलबंद नमूने को जिला आयोग और राज्य आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को भेजा जाएगा।

(4) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, सीलबंद नमूना प्राप्त करने के पश्चात् उसका परीक्षण करेगी, अपनी रिपोर्ट, पैंतालीस दिन के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो जिला आयोग और राज्य आयोग द्वारा प्रदान किया जाए, खराबी (कमी) की प्रकृति और रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए, जिला आयोग या राज्य आयोग को अग्रेषित करेगी।

11. रकम का पचास प्रतिशत जमा करने की रीति.––जहां धारा 41 के अधीन कोई अपील फाइल की जाती है, वहां उक्त धारा के द्वित्तीय परन्तुक में यथा उपबंधित अपीलार्थी द्वारा जमा की जाने वाली रकम रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित किए जाने वाले शिमला में संदेय रेखांकित (क्रॉस्ड) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में विप्रेषित की जाएगी।

12. राज्य आयोग में सदस्यों की संख्या.–राज्य आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष महिला होगी।

13. राज्य आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारिवृंद.––राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों, जो उस स्थान पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लागू हों, द्वारा विनियमित की जाएगी। ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों को संदेय वेतन राज्य सरकार के समेकित निधि से चुकता किया जाएगा।

14. राज्य आयोग द्वारा सूचना प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.––राज्य आयोग त्रैमासिक या राज्य सरकार द्वारा मामलों के लम्बन सहित कोई सूचना, जब कभी अपेक्षित हो, अनुसूची–1 में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची–1

(त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट)
उपभोक्ता आयोगों / उपभोक्ता संरक्षण उपायों का कार्यकरण
राज्य का नामः

1.	राज्य आयोग और जिला आयोग की स्थापनाः	
I	राज्य में जिला की कुल संख्या	
II	राज्य में जिला आयोगों की कुल संख्या	

(क) कुल स्थापितः				
(ख) क्रियाशीलः				
(ग) गैर–क्रियाशीलः				
(घ) जिला का नाम जिसमें अभी जिला आयोग की स्थापना की जानी हैः				
(ङ) जिलों की संख्या जिनमें जिला आयोग की स्थापना की जानी हैः				
(च) उन जिलों की संख्या जिनमें एक से अधिक जिला आयोग स्थापित किए गए हैं।	जिला का नाम		जिला आयोगों की संख्या	
III क्या राज्य आयोग क्रियाशील है	हां		नहीं	
IV पदों की संख्या और रिक्तियों की संख्या	राज्य आयोग		स्वीकृत जिला आयोग	
	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्तियों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्तियों की संख्या
(क) अध्यक्ष				
(ख) सदस्य				
(ग) रिक्त पदों के कारण और उन्हें भरने के लिए की गई कार्रवाई (पृथक् रूप से संलग्न की जाए)				

2. राज्य आयोग और जिला आयोग का कार्य निष्पादन

I (क) स्थापना काल से फाइल किए गए कुल मामले	राज्य आयोग	जिला आयोग
(ख) निपटाए गए मामले		
(ग) निर्धारित समय मानदंडों के भीतर निपटाए गए मामले		
(घ) लोक अदालत पद्धति के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या		
II लंबित मामलों का विस्तृत विवरण (मामलों की संख्या का उल्लेख करें)	राज्य आयोग	जिला आयोग
(क) तीन मास से अधिक और एक वर्ष तक		
(ख) एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक		
(ग) दो वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक		
(घ) पांच वर्ष से अधिक		
III समय मानदण्डों के भीतर निपटाए गए मामले (मामलों की संख्या दें)	राज्य आयोग	जिला आयोग
(क) 15 मार्च, 2002 के पश्चात् प्राप्त मामले		
(ख) उपरोक्त (क) के समय मानदंडों के भीतर निपटाए गए मामले (संख्या और प्रतिशत)		

3. कॉन्फनेट प्रोजैक्ट (परियोजना) का कार्यान्वयन

I कंप्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर	राज्य आयोग	जिला आयोग (संख्या)
(क) प्राप्त हुए	हां नहीं	
(ख) संस्थापित किए गए	हां नहीं	
(ग) क्रियाशील है	हां नहीं	

कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे कार्यकलाप	राज्य आयोग	जिला आयोग (संख्या)
II (क) क्या मामला निगरानी प्रणाली, संस्थापित और क्रियाशील है	हां नहीं	
(ख) क्या मामले का वास्तविक समय डाटा प्रविष्ट किया गया है	हां नहीं	
(ग) क्या वाद सूची और निर्णय को वेबसाइट पर डाला जा रहा है	हां नहीं	

4. प्रशिक्षण			
(क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में सदस्यों / अध्यक्ष का प्रशिक्षण	प्रशिक्षण योजना के अनुसार वर्ष में प्रशिक्षण किए जाने वाले	अब तक प्रशिक्षित किए गए	तिमाही के दौरान प्रशिक्षित किए गए
(ख) बी आई एस प्रशिक्षण संस्थान में राज्य / जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण			
(ग) कॉन्फनेट के अधीन प्रशिक्षण			
(क) अध्यक्ष और सदस्य			
(ख) अन्य कर्मचारिवृन्द			
(घ) कोई अन्य प्रशिक्षण			

आदेश द्वारा,
सी.पालरासू,
सचिव (खा0ना0आ0 एवं उप0 मा0)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(03)-2/2019 dated 24th August, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 24th August, 2021

No. FDS-A(3)-2/2019.—In exercise of the powers conferred by sections 2(19), 28(2)(b), 33(3), 38(2), 41, 42(3), 46(3), 70(5) and clauses (a), (g), (i), (j), (k), (l), (n), (o) and (q) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Consumer Protection (General) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.— (1) ln these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) 'Commission' means the District Commission and the State Commission, as the case may be;

(c) 'President' means the President of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(d) 'Section' means a section of the Act; and

(e) 'State Government' means the Government of Himachal Pradesh.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Place of sitting of the District Commission.—The office of the District Commission shall be located at the headquarters of the District and where the State Government decides to establish a single District Commission having jurisdiction over more Districts than one it shall notify the place and jurisdiction of the District Commission so established.

4. Working days and office hours of District Commission and State Commission.— The working days and office hours of the District Commission and the State Commission shall be the same as that of the District Courts and High Court of the State.

5. Seal and emblem.—The official seal and emblem of the District Commission and State Commission shall be such as the State Government may specify.

6. Sittings of the District Commission and the State Commission.—The President of the District Commission and State Commission shall convene sittings of that Commission as and when it may be necessary for speedy disposal of the consumer cases.

7. Public utility services to be established.—Public utility services shall be established for the purpose of Clause (19) of section 2 of the Act.

8. Number of members in District Commission.—The District Commission shall consist of a President and two members of whom at least one member or the President shall be a woman.

9. Officers and other employees of District Commission.—The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of the service of, the officers and other employees of the District Commission shall be regulated by the rules, regulations and orders as are applicable to the officers and other employees of the State Government stationed at those places. The salary payable to such officers/officials shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Govt.

10. Manner of authentication of goods by District Commission and State Commission for analysis and testing.—(1) The District Commission and State Commission may direct the

complainant to provide one or more than one sample of the goods in clean Containers with stopper properly fixed on them for the purposes of testing or analysis.

(2) On receiving the samples of such goods, the District Commission and State Commission shall seal the same and fix labels on the containers carrying the following information, namely:—

(a) The name and address of the recognized laboratory to whom sample shall be sent for analysis and test;

(b) The name and address of the District Commission and State Commission, as the case may be;

(c) The case number; and

(d) The official seal of the District Commission or the State Commission, as the case may be.

(3) The sealed sample shall be sent to the recognised laboratory by the District Commission and State Commission.

(4) The recognized laboratory shall, after receiving sealed sample examine the same, forward its report to the District Commission and State Commission within forty-five days or within such extended time as may be granted by the District Commission and State Commission, specifying the nature of the defect and date of submission of report.

11. Manner of depositing fifty percent of the amount.—Where an appeal is filed under section 41, the amount to be deposited by the appellant as provided in the second proviso to the said section shall be remitted in the form of a crossed Demand Draft drawn on a nationalised bank in favour of the Registrar, Himachal Pradesh State Consumer Commission, payable at Shimla.

12. Number of members in State Commission.—The State Commission shall consist of a President and four members out of whom at least one member or the President shall be a woman.

13. Officers and other employees of State Commission.—The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the officers and other employees of the State Commission shall be regulated by the rules, regulations and orders as are applicable to the officers and other employees of the State Government stationed at those places. The salary payable to such officers/officials shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Govt.

14. Form and manner for furnishing of information by State Commission.—The State Commission shall furnish, quarterly or as and when required by the State Government any information including pendency of cases in the form as specified in the following **Schedule I :—**

SCHEDULE-I

(Quarterly Performance Report)

Working of Consumer Commissions/Consumer Protection Measures
Name of State:

1. **Establishment of State Commission and District Commission :**		
I	Total number of Districts in State	

II	Number of District Commissions in the State		
	(a) Total Setup :		
	(b) Functional :		
	(c) Non Functional :		
	(d) Name of District where District Commission yet to be set up :		
	(e) Number of District where District Commission yet to be set up		
	(f) Number of Districts where more than one District Commission has been set up	District Name	No. of District Commissions

III	Whether State Commission functional	Yes		No	
IV	Strength and vacancies	State Commission		Sanctioned District Commissions	
		Sanctioned strength	vacancies	Sanctioned strength	Vacancies
	(a) President				
	(b) Members				
	(c) Reason for Vacancies and Action taken to fill up the same (to be enclosed separately)				

2.	**Performance of State Commission and District Commission**		
I	(a) Total cases filed since inception	State Commission	District Commission
	(b) Cases disposed of		
	(c) Cases disposed of within prescribed time norms		
	(d) Number of cases disposed of by Lok Adalat Method		
II	Detailed Break up of cases pending (give number of cases)	State Commission	District Commission
	(a) Over 3 months upto 1 year		
	(b) Over 1 year upto 2 years		
	(c) Over 2 years upto 5 years		
	(d) Over 5 years		
III	Cases disposed of within time norms (give number)	State Commission	District Commission
	(a) Cases received after 15th March, 02		
	(b) Cases disposed of within time norms out of (a) above (Number and %)		
3. **Implementation of Confonet Project**			
I	Computer Hardware/Software has	State Commission	District

			Commission (Numbers)
	(a) been received	Yes No	
	(b) been installed	Yes No	
	(c) been functional	Yes No	
II	Activities being done through computers	State Commission	District Commission (Numbers)
	(a) Is case Monitoring System Installed and Operational;	Yes No	
	(b) Has the live case data been entered?	Yes No	
	(c) Whether cause list and judgement being posted on the website.	Yes No	

4.	**Training**			
(a)	Training of Members/President in Indian Institute of Public Administration	To be trained in the year as per training plan	Trained so far	During the quarter
(b)	Training of State/District level Officers in BIS Training Institute			
(c)	Training under Confonet			
	(a) President and Members			
	(b) Other Staff			
(d)	Any other Training			

By order,
C. PAULRASU,
Secretary (FCS & CA).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 अगस्त, 2021

संख्या एफ.डी.एस.–ए(3)–2 / 2019.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (ङ) और (च) के साथ पठित धारा

6(2)(ख), 6(4), 8(2)(ख), 8(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**––(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से, राज्य परिषद् और जिला परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और

(ग) "राज्य परिषद्" और "जिला परिषद्" से, अधिनियम की क्रमशः धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. **राज्य परिषद् की संरचना.**––राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिषद् की स्थापना करेगी, जिसमें तेरह से अनधिक निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामले का प्रभारी मन्त्री, राज्य परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ख) विधानसभा के दो सदस्य जिनमें से एक महिला सदस्य होगी;

(ग) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले का प्रभारी प्रशासनिक सचिव;

(घ) रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हिमाचल प्रदेश;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उपभोक्ता संगठनों के तीन से अनधिक प्रतिनिधि;

(च) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्त्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, व्यापार या उद्योग–जगत में से उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम सिद्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले तीन से अनधिक प्रतिनिधि जिनमें से कम से कम एक महिला प्रतिनिधि होगी; और

(छ) निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश, राज्य परिषद् का सदस्य–सचिव होगा।

4. **राज्य परिषद् का कार्यकाल.**––राज्य परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगाः

परन्तु राज्य परिषद् तीन मास की और अवधि तक या इसका पुनर्गठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पूर्वतर हो, कार्य करती रहेगी।

5. **राज्य परिषद् की बैठकें, इसके उद्देश्य और कारबार का संव्यवहार.**––(1) राज्य परिषद का मुख्यालय शिमला में होगा।

(2) राज्य परिषद् की बैठकें जब भी आवश्यक हो, आयोजित की जांएगी, किन्तु प्रत्येक वर्ष दो से अन्यून बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(3) राज्य परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तारीख से कम–से–कम पंद्रह दिन पहले डाक द्वारा या ई–मेल के माध्यम से त्वरित संचार को सुकर बनाने के लिए लिखित सूचना देते हुए बुलाई जा सकेगी।

(4) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की सूचना द्वारा बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदें संसूचित की जाएंगी।

(5) राज्य परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

(6) किसी रिक्ति के होने अथवा राज्य परिषद् के गठन में किसी त्रुटि के होने मात्र से राज्य परिषद् की कोई भी कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

6. **जिला परिषद् की संरचना.––**हिमाचल प्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिला परिषद् की स्थापना करेगी, जिसमें दस से अनधिक निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) सम्बद्ध जिला का उपायुक्त, जिला परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ख) अतिरिक्त उपायुक्त या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला परिषद् का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) सम्बद्ध जिला उपभोक्ता आयोग का एक सदस्य, जिसे उस आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उपभोक्ता संगठनों के दो से अनधिक प्रतिनिधि;

(ङ) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार या उद्योग–जगत में से उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम सिद्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले दो से अनधिक प्रतिनिधि जिनमें से कम से कम एक महिला प्रतिनिधि होगी; और

(च) जिला का जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला परिषद् का सदस्य–सचिव होगा।

7. **जिला परिषद् का कार्यकाल.––**जिला परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगाः

परन्तु जिला परिषद् तीन मास की और अवधि तक या इसका पुनर्गठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पूर्वतर हो, कार्य करती रहेगी।

8. **जिला परिषद् की बैठकें, इसके उद्देश्य और कारबार का संव्यवहार.––**(1) जिला परिषद् जब भी आवश्यक हो बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक वर्ष दो से अन्यून बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(2) जिला परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तारीख से कम–से–कम पंद्रह दिन पहले डाक द्वारा या ई–मेल के माध्यम से त्वरित संचार को सुकर बनाने के लिए लिखित सूचना देते हुए बुलाई जा सकेगी।

(3) जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक की सूचना द्वारा बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदें संसूचित की जाएंगी।

(4) जिला परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

(5) जिला परिषद् की कोई कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के होने या जिला परिषद् के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

9. **व्यय और बैठक फीस की प्रतिपूर्ति.**––राज्य परिषद् और जिला परिषद् के गैर–सरकारी सदस्य राज्य परिषद् या जिला परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए प्रति बैठक एक हजार रुपए के मानदेय और टैक्सी के किराए के लिए हकदार होंगे।

आदेश द्वारा,

सी.पालरासू,
सचिव (खा0ना0आ0 एवं उप0 मा0)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A (03)-02/2019 dated 24-8-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th August, 2021

No. FDS-A(3)-2/2019.—In exercise of the powers conferred by sections 6(2)(b), 6(4), 8(2)(b), 8(4) read with clauses (c), (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Consumer Protection (State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) ln these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the State Council and District Council;

(c) "State Council" and "District Council" means the State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council established under sub-section (1) of section 6 and sub-section (1) of section 8, respectively of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Composition of State Council.—The Government of H.P. shall, by notification in the Official Gazette, establish the State Council which shall consist of the following members, not exceeding thirteen, namely: —

(a) The Minister-in-charge of Consumer Affairs in the State Government who shall be the Chairperson of the State Council;

(b) Two Members of the Legislative Assembly of whom at least one shall be a woman;

(c) The Administrative Secretary-in-charge of Consumer Affairs in the State Government;

(d) The Registrar, H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission;

(e) Representatives of consumer organisations not exceeding three, to be nominated by the State Government;

(f) Representatives with proven expertise and experience who are capable of representing consumer interests, drawn from amongst consumer organisations, consumer activists, research and training organisations, academicians, trade or industry, not exceeding three, of whom at least one shall be a woman; and

(g) The Director (FCS & CA), Himachal Pradesh shall be the Member-Secretary of the State Council.

4. Term of State Council.—The term of the State Council shall be three years:

Provided that the State Council shall continue to function for a further period of three months or till it is reconstituted, whichever is earlier.

5. Meetings of State Council, its objects and transaction of business.—(1) The Headquarter of the State Council shall be at Shimla.

(2) The meetings of the State Council shall be held as and when necessary but not less than two meetings shall be held every year.

(3) A meeting of the State Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member at least fifteen days before the intended date of the meeting by post, or through e-mail to facilitate speedy communication.

(4) The notice of every meeting of the State Council shall intimate the time, date, and place of the meeting and the items of agenda for the meeting.

(5) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the State Council except with the permission of the Chairperson.

(6) No proceedings of the State Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the State Council.

6. Composition of District Council.—The Government of Himachal Pradesh shall, by notification in the Official Gazette, establish the District Council which shall consist of the following members, not exceeding ten, namely: —

(a) Deputy Commissioner of the concerned District who shall be the Chairperson of the District Council;

(b) Additional Deputy Commissioner or Additional District Magistrate who shall be the Vice Chairperson;

(c) A Member of the concerned District Consumer Commission nominated by the President of that Commission;

(d) Representatives of consumer organisations not exceeding two, to be nominated by the State Government;

(e) Representatives with proven expertise and experience who are capable of representing consumer interests, drawn from amongst consumer organisations, consumer activists, research and training organisations, academicians, farmers, trade or industry, not exceeding two, of whom at least one shall be a woman; and

(f) District Controller, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs of the District who shall be the Member-Secretary of the District Council.

7. Term of District Council.—The term of the District Council shall be three years:

Provided that the District Council shall continue to function for a further period of three months or till it is reconstituted, whichever is earlier.

8. Meetings of District Council, its objects and transaction of business.—(1) The District Council shall meet as and when necessary but not less than two meetings shall beheld every year.

(2) A meeting of the District Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member at least fifteen days before the intended date of the meeting by post, or through e-mail to facilitate speedy communication.

(3) The notice of every meeting of the District Council shall intimate the time, date, and place of the meeting and the items of agenda for the meeting.

(4) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the District Council except with the permission of the Chairperson.

(5) No proceedings of the District Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the District Council.

9. Reimbursement of expenses and sitting fees.—Non-official members of the State Council and District Council shall be entitled to honorarium of rupees one thousand per sitting plus taxi fare for the purpose of attending meetings of State Council and District Council.

By order,

C. PAULRASU,
Secretary (FCS & CA).

———————————

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 अगस्त, 2021

संख्या एफ.डी.एस.–ए(3)–2 / 2019.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 की उपधारा (2) के खण्ड (त) के साथ पठित धारा 74(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**––(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग अभिप्रेत है; और

(ग) "मध्यस्थता प्रकोष्ठ" से, अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित मध्यस्थता प्रकोष्ठ अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. **मध्यस्थता प्रकोष्ठ.**––(1) किसी जिला आयोग और राज्य आयोग में स्थापित प्रत्येक मध्यस्थता प्रकोष्ठ में, उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर मध्यस्थों का एक पैनल होगा।

(2) मध्यस्थता प्रकोष्ठ में उतनी संख्या में सहायक कर्मचारिवृंद होंगे, जितने राज्य आयोग / ज़िला आयोग का अध्यक्ष राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित करे तथा सरकार आयोग द्वारा अपेक्षित समस्त प्रशासनिक सहायता और अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

आदेश द्वारा,
सी.पालरासू,
सचिव (खा0ना0आ0 एवं उप0 मा0)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A (03)-02/2019 dated 24th August, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India] .

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th August, 2021

No. FDS-A(3)-2/2019.—In exercise of the powers conferred by section 74(3) read with clause (p) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Consumer Protection (Mediation) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) ln these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) "Commission" means District Commission or State Commission, as the case may be; and

(c) "Mediation cell" means a consumer mediation cell established under sub-section (1) of section 74 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Mediation Cell.—(1) Every Mediation Cell set up in a District Commission and the State Commission shall have a panel of mediators on the recommendation of a selection committee consisting of the President and a member of that Commission.

(2) The Mediation Cell shall have such supporting staff as may be decided by the President of State Commission/District Commission in consultation with the State Government and the Government shall provide all administrative assistance and infrastructure facilities required by the Commission.

By order,

C. PAULRASU,
Secretary (FCS & CA).

———————

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 अगस्त, 2021

संख्या एफ.डी.एस.–(ए)3–2 / 2019.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 30 और 44 और धारा 102 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) और (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग / जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन और सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार और लागू होना.––ये नियम उन पदधारियों को लागू होंगे, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) के प्रवर्तन की तारीख को या इसके पश्चात् नियुक्त हुए हैं।

3. परिभाषाएं.––(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) 'सदस्य' से, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है,

(ग) 'अध्यक्ष' से, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और

(घ) 'राज्य सरकार' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

4. जिला आयोग के अध्यक्ष को संदेय वेतन.––(1) यदि कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है, जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसे वेतन, जो वह उसकी ऐसी नियुक्ति की तारीख को प्राप्त कर रहा था, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) यदि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसे वेतन का हकदार होगा जैसा राज्य के जिला न्यायाधीश को उसके द्वारा आहरित पैन्शन की कुल रकम को घटाकर, अनुज्ञेय है।

(3) यदि जिला आयोग का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश बनाए जाने के लिए अर्हित है तो वह राज्य के जिला न्यायाधीश के वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेने का हकदार होगा।

5. जिला आयोग के सदस्यों को संदेय पारिश्रमिक / मानदेय.––जिला आयोग के सदस्यों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित समेकित पारिश्रमिक / मानदेय संदत्त किया जाएगा।

6. राज्य आयोग के अध्यक्ष को संदेय वेतन.––(1) यदि कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसे वेतन, जो वह उसकी ऐसी नियुक्ति के समय प्राप्त कर रहा था, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) यदि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसे वेतन का हकदार होगा जैसा राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को, उसके द्वारा आहरित पैन्शन की कुल रकम को घटाकर, अनुज्ञेय है।

7. राज्य आयोग के सदस्यों को संदेय पारिश्रमिक / मानदेय.––राज्य आयोग के सदस्यों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति बैठक दो हजार पांच सौ रुपए का समेकित पारिश्रमिक / मानदेय संदत्त किया जाएगा।

8. चिकित्सा स्वस्थता.––किसी भी व्यक्ति को जिला आयोग या राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा उसे चिकित्सक दृष्टया स्वस्थ घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9. मकान किराया भत्ता.––जिला आयोग और राज्य आयोग का अध्यक्ष राज्य सरकार के तत्स्थानी प्रास्थिति के ग्रेड–I के अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

10. यात्रा और दैनिक भता.––(1) जिला आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सरकारी दौरे पर राज्य सरकार के तत्स्थानी प्रास्थिति के ग्रेड–I के अधिकारियों की हकदारी के समरूप यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होंगे।

(2) जिला आयोग और राज्य आयोग का अध्यक्ष सम्बद्ध यान (अटैच्चड व्हीकल) का हकदार होगा।

11. छुट्टी और चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाएं.––जिला आयोग और राज्य आयोग का अध्यक्ष राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू उपबंधों के अनुसार छुट्टी, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के लिए हकदार होगा।

12. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.––जिला आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपनी परिसम्पत्तियां, और अपने दायित्वों और वित्तीय तथा अन्य हितों की घोषणा करेंगे / करेंगी।

13. सेवा की अन्य शर्तें.––(1) अध्यक्ष की सेवा के निबन्धन और शर्तें, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार के तत्स्थानी प्रास्थिति के 'ग्रेड–I' अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(2) अध्यक्ष, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग का पद छोड़ने के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग में व्यवसाय (प्रैक्टिस) नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग में इन हैसियतों में कृत्य करते हुए माध्यस्थम का कोई भी कार्य नहीं करेगा।

(4) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष उस तारीख, जिसको वह पद पर नहीं रहता है, से दो वर्ष की अवधि के लिए, किसी व्यक्ति, जो जिला आयोग या राज्य आयोग की कार्यवाहियों में पक्षकार रहा है, से इसके प्रबन्धन या प्रशासन से सम्बद्ध कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगाः

परन्तु इन नियमों में अन्वर्दिष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किसी निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होगी।

14. पद और गोपनीयता की शपथ.––अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप–1 में पद की शपथ और प्ररूप–2 में गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

15. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्ते राज्य की संचित निधि में से चुकता किए जाएंगे।

16. जिला आयोग या राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबन्धन और शर्तें उनके पद के कार्यकाल के दौरान प्रतिकूलतः परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

आदेश द्वारा,

सी. पालरासू,
सचिव (खा0ना0आ0 एवं उप0 मा0)।

उपाबन्ध

नियम (14) देखें

प्ररूप–1

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररुप

मैं....., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,...../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग..... .....का अध्यक्ष / सदस्य के रुप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं / ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग / जिला आयोग के अध्यक्ष / सदस्य

के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा तथा किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूंगा तथा मैं संविधान और देश की विधि की रक्षा करूंगा।

प्ररूप–2

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं....., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग...../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग..... .....का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए यथाअपेक्षित के सिवाय, मेरे विचाराधीन प्रस्तुत किए गए अथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात होते हुए, किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं रूरुंगा।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A (03)-02/2019 dated 24th August, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India] .

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th August, 2021

No. FDS-A(3)-2/2019.—In exercise of the powers conferred by sections 30 and 44 and clauses (h) and (m) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Consumer Protection (Salary and other terms and conditions of service of the President and Members of the District Commission/State Commission) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Scope and applicability.—These rules shall apply to those incumbents who are appointed on or after coming into force of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) in the State of Himachal Pradesh.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) 'Member' means a member of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(c) 'President' means the President of the District Commission or the State Commission, as the case may be; and

(d) 'State Government' means Government of Himachal Pradesh.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

4. Salaries payable to President of District Commission.—(1) If a person who is District Judge is appointed as the President of the District Commission then he shall be entitled to receive the salary which he was getting on the date of his such appointment.

(2) In case the retired District Judge has been appointed as President of the District Commission then he shall be entitled to such salary as is admissible to District Judge of the State reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(3) If the President of the District Commission is a person qualified to be District Judge then he shall be entitled to salary to the minimum of the pay scale of the District Judge of the State.

5. Remuneration/honorarium payable to members of District Commission.—The members of the Commission shall be appointed on part-time basis and shall be paid a consolidated remuneration/honorarium as may be prescribed from time to time by the State Government.

6. Salaries payable to President of the State Commission.—(1) If a person who is Judge of the High Court is appointed as President of the State Commission then he shall receive the salary which he was receiving at the time of his such appointment.

(2) In case the retired Judge of the High Court has been appointed as President of the State Commission then he shall be entitled to such salary as is admissible to the sitting Judge of High Court of the State reduced by the gross amount of pension drawn by him.

7. Remuneration/honorarium payable to members of State Commission.—The members of the State Commission shall be appointed on part-time basis and shall be paid a consolidated remuneration/ honorarium of rupees two thousand five hundred per sitting.

8. Medical fitness.—No person shall be appointed as President of the District Commission and State Commission unless he/she is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

9. House rent allowance.—The President of the District Commission and State Commission shall be entitled to house rent allowance at the same rate as is admissible to 'Grade-I' Officer of the State Government of a corresponding status.

10. Travelling and daily allowance.—(1) The President and the members of the District Commission and State Commission shall be entitled to travelling and daily allowances on official tours equivalent to the entitlements of 'Grade-I' Officers of the State Government of corresponding status.

(2) President of the District Commission and State Commission shall be entitled to an attached vehicle.

11. Leave and medical treatment and hospital facilities.—The President of the District Commission and the State Commission shall be entitled to leave, medical treatment and hospital facilities as per the provisions as are applicable to the employees of the State Government.

12. Declaration of Financial and other Interests.—The President and Member of the District Commission and State Commission shall, before entering upon his/her office, declare his/her assets, and his/her liabilities and financial and other interests.

13. Other conditions of service.—(1) The terms and conditions of service of the President with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a 'Grade-I' Officer of the State Government of a corresponding status.

(2) The President shall not practise before the National Commission, the State Commission or the District Commission after demitting the office of the District Commission or the State Commission, as the case may be.

(3) The President or member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the District Commission or the State Commission, as the case may be.

(4) The President of the District Commission or the State Commission, as the case may be, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the District Commission or the State Commission:

Provided that nothing contained in these rules shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

14. Oaths of office and secrecy.—Every person appointed to be the President and Member shall, before entering upon his/her office, make and subscribe an oath of office in Form-I and oath of secrecy in Form-II appended to these rules.

15. The salary, remunerations and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State.

16. The terms and conditions of the service of the President and the members of the District Commission and the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

By order,

C. PAULRASU,
Secretary (FCS & CA).

ANNEXURE

[*See* Rule 14]

FORM-I

Form of Oath of Office for the President and Member of the State Commission and District Commission

I,....., having been appointed as the President/ Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission,……../District Consumer Disputes Redressal Commission, ……..do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State Commission/District Commission to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

FORM-II

Form of Oath of Secrecy for the President and Member of the State Commission and District Commission

I,....., having been appointed as the President/Member of the State Consumer Disputes Redressal Commission,……. /District Consumer Disputes Redressal Commission, …… do

solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the State Commission/District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -171 002, the 16th August, 2021

No. FDS-C(17)-1/2021.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to form the e- Governance Society, Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department (eGS), registered under the provisions of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 *vide* registration No. 834/2014, dated 22-07-2014. The formation of the e-Governance Society (eGS) shall be deemed effective from the date of its registration *i.e.* 22-07-2014. The composition of Governing Body of eGS is as under:—

Sl. No.	Designation & Address	Remarks
1.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (FCS&CA) to the Govt. of H.P., Shimla-2.	President
2.	Special Secretary (Finance-Expenditure) to the Govt. of H.P., Shimla-2.	Member
3.	Managing Director, H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd. Shimla-9.	Member
4.	Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9	Member-Secretary
5.	Additional/Joint Director (Admin) (HAS) Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9.	Member
6.	Joint Director/Deputy Director, Department of IT, H.P., Shimla-13	Member
7.	Joint Director/Deputy Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9 looking after ePDS in FCS&CA deptt.	Member
8.	Deputy Controller (F&A), Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9	Treasurer

The composition of Executive Body of eGS is as under:—

Sl. No.	Designation & Address	Remarks
1.	Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9	President
2.	Additional/Joint Director (Admin) (HAS) Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9.	Member
3.	Joint Director/Deputy Director, Department of IT, H.P., Shimla-13	Member
4.	Joint Director/Deputy Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9 looking after ePDS in FCS&CA deptt.	Member-Secretary
5.	Deputy Controller (F&A), Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9.	Treasurer

By order,
C. PAULRASU,
Secretary (FCS&CA).

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate Sadar, District Bilaspur, H.P.**

In the matter of

1. Sh. Krishan Pal s/o Sh. Ram Saran, r/o Village Lunas, House No. 70/1, Tehsil Ram Shehar, District Solan (H.P.)

2. Jyoti Devi d/o Sh. Heera Lal r/o V.P.O. Nand, Tehsil Ramshehar, Distt. Solan (H.P.)

Versus

General Public

Subject:-Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act.

Sh. Krishan Pal & Smt. Jyoti Devi have filed an application under Special Marriage Act. 1954 (Central Act 43 of 1954) alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnize their marriage on 22-09-2020 at Durga Mata Mandir, Changer Sector Bilaspur,Himachal Pradesh.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this mariage, can file the objection personally or in written before this court on or before 28-08-2021. The obejections if any, received after 28-08-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and the seal of the court on dated 30-07-2021.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum- *Sub-Divisional magistrate, Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh.*

न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल, कार्याकारी दण्डाधिकारी एवं नायब–तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)

श्री सन्नी वर्मा पुत्र केवल चन्द, वासी टीका टिक्कर उपरला, डाकघर टिक्कर खतरियां, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। ...प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ...प्रतिवादी।

विषय.–राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री सन्नी वर्मा पुत्र केवल चन्द, वासी टीका टिक्कर उपरला, डाकघर टिक्कर खतरियां, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में सन्नी वर्मा दर्ज है जो की सही है। परन्तु पटवार वृत्त टिक्कर खतरियां के रजस्व रिकार्ड में उसका नाम सन्नी कुमार दर्ज है जोकी गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 27–08–2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28–07–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Vijay Kumar, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Shubham s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Sharwin, P. O. Uttap, Tehsil Galore, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Rubby Sharma d/o Sh. Ashwani Kumar, r/o Village Jandana, P. O. Jatehri, Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 15 &16 of Special Marriage Act, 1954.

Shubham s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Sharwin, P. O. Uttap, Tehsil Galore, Distt. Hamirpur (H.P.) & Rubby Sharma d/o Sh. Ashwani Kumar, r/o Village Jandana, P. O. Jatehri, Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-06-2021 at Mandir of Mata Mansha Devi Chamunda, Distt. Kangra (H.P.) and they are living as husband and wife since then hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 28-08-2021 at 10.00 A.M. it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 15-07-2021 under my hand and seal of the court.

Seal. VIJAY KUMAR, HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Vijay Kumar, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Ranjit Singh s/o Sh. Bhuri Singh, r/o Village Pukharu Palakhar, P. O. Manjhiar, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Aruna Devi d/o Sh. Bishanu Ram, r/o Village Tilla, P. O. Bhiambi, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) ..*Applicant.*

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 15 &16 of Special Marriage Act, 1954.

Ranjit Singh s/o Sh. Bhuri Singh, r/o Village Pukharu, P. O. Manjhiar, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) & Aruna Devi d/o Sh. Bishanu Ram, r/o Village Tilla, P. O. Bhiambi, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-02-1989 at Pukharu Palakhar, P.O. Manjhiar, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) and they are living as husband and wife since then hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 31-08-2021 at 10.00 A.M. it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 28-07-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIJAY KUMAR, HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

1. Karan Singh Aged 27 years s/o Sh. Partap Singh, r/o Village Gadru, P.O. Sulkhan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Kiran Devi Aged 25 years d/o Sh. Kakku Ram, House No. 180, Surya Colony, Ward No. 06, Paonta Sahiv, District Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Karan Singh Aged 27 years s/o Sh. Partap Singh, r/o Village Gadru, P.O. Sulkhan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Kiran Devi Aged 25 years d/o Sh. Kakku Ram, House No. 180,

Surya Colony, Ward No. 06, Paonta Sahiv, District Sirmaur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage ceremony on 19-09-2020 at Prachin Pasupati Nath Shiv Mandir, Panchkulla, Haryana as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 31-08-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-07-2021 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Pankaj Kumar aged 21 years s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Koon, P.O. Tourkhola, Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.) at present r/o Sh. Piar Chand s/o Sh. Findi Ram, V.P.O. Chouri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Priti Kumari aged 19 years d/o Sh. Om Chand, r/o Village Devgarh, P.O. Cholangarh, Tehsil Sandhole, District mandi (H.P.) at present r/o Sh. Piar Chand s/o Sh. Findi Ram, V.P.O. Chouri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Pankaj Kumar aged 21 years s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Koon, P.O. Tourkhola, Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.) at present r/o Sh. Piar Chand s/o Sh. Findi Ram, V.P.O. Chouri, Tehsil Sujanpur District Hamirpur (H.P.) and Priti Kumari aged 19 years d/o Sh. Om Chand, r/o Village Devgarh, P.O. Cholangarh, Tehsil Sandhole, District mandi (H.P.) at present r/o Sh. Piar Chand s/o Sh. Findi Ram, V.P.O. Chouri, Tehsil Sujanpur District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-08-2021. The objections received after 31-08-2021 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-07-2021 under my hand and seal of the court.

Seal. SHILPI BEAKTA, H.A.S.,

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Mukesh Kumar aged 29 years s/o Sh. Sohan Lal, r/o Village Darati, P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Kiran Devi aged 19 years d/o Sh. Basant Lal, V.P.O. Bhattu, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Mukesh Kumar aged 29 years s/o Sh. Sohan Lal, r/o Village Darati, P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Kiran Devi aged 19 years d/o Sh. Basant Lal, V.P.O. Bhattu, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-08-2021. The objections received after 31-08-2021 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-07-2021 under my hand and seal of the court.

Seal. SHILPI BEAKTA, H.A.S.,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Pradeep Kumar aged 32 years s/o Sh. Puran Chand, r/o Village Kachh, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Babita Devi aged 28 years d/o Shri Shiv Kant Mishra, Village Bhartipur, P.O. Vallipur, PS Motigarpur, District Sultanpur (U.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Pradeep Kumar aged 32 years s/o Sh. Puran Chand, r/o Village Kachh, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Babita Devi aged 28 years d/o Shri Shiv Kant

Mishra, Village Bhartipur, P.O. Vallipur, PS Motigarpur, District Sultanpur (U.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 18-07-2021 at Village Kachh, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-08-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-07-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

SHILPI BEAKTA, H.A.S.,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री श्याम लाल पुत्र श्री चमन लाल, निवासी उग्राहला उपरला, डाकघर लग, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल उग्राहला उपरला, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री श्याम लाल पुत्र श्री चमन लाल, निवासी महाल उग्राहला उपरला, डाकघर लग, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड व स्कूल रिकार्ड में श्याम लाल पुत्र चमन लाल है। जबकि राजस्व रिकार्ड महाल उग्राहला उपरला में उसका नाम शाम लाल पुत्र चमन लाल पुत्र गुलाबा दर्ज है जो सही न है । प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–08–2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर / एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 03–08–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

In the Court of Shri B. R. Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Sh. Mohan Lal s/o Sh. Kali Ram, r/o Village Bashool, P.O. Shakrah, Sub-Tehsil Dhammi, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. *Respondent.*

Whereas Sh. Mohan Lal s/o Sh. Kali Ram, r/o Village Bashool, P.O. Shakrah, Sub-Tehsil Dhammi, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named—Miss Kareena d/o Sh. Mohan Lal, r/o Village Bashool, P.O. Shakrah, Sub-Tehsil Dhammi, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy.-*cum*-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Shakrah, Sub-Tehsil Dhamim, District Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Miss Kareena	Daughter	14-03-2011

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Secy.-*cum*-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Shakrah, Tehsil Dhammi, District Shimla (H.P.), may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 19-08-2021 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Abhinav s/o Sh. Roshan Lal, Resident of House No. 17/8, Lakshi Bhawan, May Villa Old Bus Stand, Shimla, Tehsil and District Shimla-171 001, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Abhinav s/o Sh. Roshan Lal, Resident of House No. 17/8, Lakshi Bhawan, May Villa Old Bus Stand, Shimla, Tehsil and District Shimla-171001, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of my grant father Late Sh. Kuda Ram (DOD-03-10-1997) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 16th August, 2021.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Abhinav s/o Sh. Roshan Lal, Resident of House No. 17/8, Lakshi Bhawan, May Villa Old Bus Stand, Shimla, Tehsil and District Shimla-171001, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Abhinav s/o Sh. Roshan Lal, Resident of House No. 17/8, Lakshi Bhawan, May Villa Old Bus Stand, Shimla, Tehsil and District Shimla-171001, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of my grant mother Late Smt. Dwarku (DOD-29-02-2000) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 16th August, 2021.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Abhinav s/o Sh. Roshan Lal, Resident of House No. 17/8, Lakshi Bhawan, May Villa Old Bus Stand, Shimla, Tehsil and District Shimla-171001, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Abhinav s/o Sh. Roshan Lal, Resident of House No. 17/8, Lakshi Bhawan, May Villa Old Bus Stand, Shimla, Tehsil and District Shimla-171001, Himachal Pradesh has preferred an

application to the undersigned for registration of date of death of my mother Late Smt. Krishna Sood (DOD-02-12-2001) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 16th August, 2021.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

In the Court of Addl. District Registrar of Marriage, Sub-Division Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh

1. Sh. Tanuj Singh s/o Sh. Bakshish Singh, r/o V.P.O. Thathal, Tehsil Amb, District Una (H.P.).
2. Smt. Neha Chauhan d/o Sh. Bal Singh Chauhan, r/o Village Rohtan, P.O. Mandal, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of marriage.

Sh. Tanun Singh and Smt. Neha Chauhan has filed an application for Registration of Marriage u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other documents in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage about two month ago *i.e.* 30-05-2021.

Therefore, you are informed through this notice that any person who has any objection regarding registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 13-09-2021. The objections received after 13-09-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-08-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Addl. District Registrar of Marriage,
Sub-Division Rohru, District Shimla,
Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mini Rawat d/o Late Sh. Ram Singh Rawat, r/o Circular Road, Bindal Colony, Tehsil & District Solan (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Mini Rawat d/o Late Sh. Ram Singh Rawat, r/o Circular Road, Bindal Colony, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of her birth *i.e*. 29-10-1992 at Guru Nanak Building, Near Thodo Ground, Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Mini Rawat d/o Late Sh. Ram Singh Rawat, r/o Circular Road, Bindal Colony, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 30-08-2021 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 31st day of July, 2021.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Biru s/o Sh. Kala Ram, Ward No. 4, Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Biru s/o Sh. Kala Ram, Ward No. 4, Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and

Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her daughter namely Anshika *i.e*. 16-01-2017 at Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Anshika d/o Sh. Biru s/o Sh. Kala Ram, Ward No. 4, Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 30-08-2021 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 31st day of July, 2021.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Biru s/o Sh. Kala Ram, Ward No. 4, Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Biru s/o Sh. Kala Ram, Ward No. 4, Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his son namely Rajveer *i.e*. 12-03-2015 at Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Rajveer s/o Sh. Biru s/o Sh. Kala Ram, Ward No. 4, Near DMR office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 30-08-2021 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 31st day of July, 2021.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Barkha w/o Sh. Sanjay, r/o Near Shiv Mandir, Village Kothon, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Barkha w/o Sh. Sanjay, r/o Near Shiv Mandir, Village Kothon, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his son namely Ashish *i.e*. 12-01-2019 at Village Kothon, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Kathon.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Ashish s/o Sh. Sanjay, r/o Near Shiv Mandir, Village Kothon, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-09-2021 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of August, 2021.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 13/2021 Date of Institution : 30-06-2021 Date of Decision: 30-08-2021

Sh. Dayal Chand s/o Shri Nand Ram, r/o Village Nichli Sandholi, P.O. Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Dayal Chand s/o Shri Nand Ram, r/o Village Nichli Sandholi, P.O. Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death

Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Rakesh Kumar was born on 26-10-1984 at Village Nichli Sandholi, P.O. Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. but his birth could not be entered in the records of G.P. Haripur Sandholi within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the G.P. Haripur Sandholi , Distt. Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding birth of namely Rakesh Kumar s/o Sh. Dayal Chand may file their, objection in this court on or before 30-08-2021 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 30th day of June, 2021.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan, (H P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan exercising the powers of Marriage Officer, Kandaghat, Distt. Solan, H.P

In Ref. :

1. Sh. Shikhar Sharma son of Sh. Dinesh Chander Sharma, resident of Flat No. 001, Block C-3, Rail Vihar, VIP Marg, Jirakpur, SAS Nagar, Punjab.

2. Smt. Samata Ahluwalia daughter of Sh. Harbans Ahluwalia, resident of Village Mangna, Post Office Delgi, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P. .....*Applicants.*

VS

General Public ....*Respondent.*

Notice

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from in this court from Sh. Shikhar Sharma son of Sh. Dinesh Chander Sharma, resident of Flat No. 001, Block C-3, Rail Vihar, VIP Marg, Jirakpur, SAS Nagar, Punjab (Husband) and Smt. Samata Ahluwalia daughter of Sh. Harbans Ahluwalia, resident of Village Mangna, Post Office Delgi, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P. (wife).

If there is any objections on this marriage, the objection in person or through counsel can be submitted to this court on or before 31-08-2021 otherwise the marriage will be registered.

Issued on this 23rd July, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal. *Sd/-*

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kandaghat, District Solan, H. P.

CHANGE OF NAME

I, Hemant Singh s/o Late Sh. Rattan Singh, Deputy District Attorney of Prosecution Department, Government of H.P. permanent r/o 167/10, Katcha Tank, Nahan, Distt. Sirmaur H.P. have changed my name from Hemant Singh to Hemant Singh Chaudhary.

HEMANT SINGH,
s/o Late Sh. Rattan Singh,
Permanent r/o 167/10, Katcha Tank,
Nahan, District Sirmaur (H.P.).

Change of Name

I, Madan Lal s/o Late Sh. Chunju Ram r/o Village Charuru, P.O. Ghallaur, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P. have changed my name to Madan Lal Sharma. The same is for the information of all concerned and future purposes.

Madan Lal,
s/o Late Sh. Chunju Ram r/o Village Charuru,
P.O. Ghallaur, Tehsil Jawalamukhi,
District Kangra, H.P.

Change of Name

I, Pinki Devi *alias* Tripta Devi wife of Madan Lal Sharma r/o village Charuru, P.O. Ghallaur, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P. have changed my name to Tripta Shama. The same is for the information of all concerned and future purposes.

Pinki Devi,
alias Tripta Devi wife of Madan Lal Sharma r/o village Charuru,
P.O. Ghallaur, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है